दिनांक 9 जुलाई, 1985

सं.स्रो.वि/रोहतक/78-85/28480--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मोहन स्पीनिंग मिल, 'रोहतक के श्रमिक श्री मोती लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यानिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, श्रव, श्रोद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिसूचना सं 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक कि नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी श्रिधिसूचना की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :--

क्या श्री मोती लाल की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.श्रो.वि/रोहतक/21-85/28487.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. प्रबन्धक निर्देशक हरियाणा स्टेंट हैन्डलूम एण्ड हैन्डीकापट कारपोरेशन लि., एस.सी.श्रो. नं. 147-148, सैक्टर-17, चण्डीगढ़, (2) हरियाणा स्टेंट हैन्डलूम हैन्डीकापट कारपोरेशन लि., सुमारी बुनाई केन्द्र, सांम्पला के श्रीमक श्री केहर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, ग्रब, श्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वार प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रिधिसूचना की धारा 7 के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :--

क्या श्री केहर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. म्रो वि/रोहतक/38-85/28495 -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में. प्रशासक नगरपालिका, रोहतक के श्रीमिक श्री राम रत्न सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कीई श्रौद्योगिक विवाद है;

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याधनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, ग्रब, श्रोद्योगिक विवाद श्रिधिनियम 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी श्रिधिसूचना की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निनिष्ट करने हैं जो कि उक्त श्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री राम रत्न सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ग्रो.वि./रोहतक/ 231-84/ 28509. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. 1. निदेशके शिक्षा विभाग (स्कूलज), हरियाणा, वण्डीगढ़, 2. मुख्य ग्रध्यापिका राजकीय उच्चविद्यालय, रोहतक, के श्रमिक श्रीमती सन्तरा देवी तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल बिवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रधिसूचना सं 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर,

1970 के साथ गठित सरकारी ग्रधिसूचना की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :---

क्या श्रीमती सन्तरा देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं स्रो वि /एफ.डी /64-85/28451. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं प्रिन्टर्ज हाऊस प्रा.लि., 22/1, मथुरा रोड़, बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री रेबाधर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद , है ;

ग्रौर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यवाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415/3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री रेवाधर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं ग्रो वि./रोहतक/66-85/28465.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. पारले बिस्कुट प्रा.लि., बहादुर-गढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री राजबीर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 निवाद प्रस्त पा उससे प्रतिक के साथ गठित सरकारी श्रधिसूचना की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवाद प्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेंतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :---

क्या श्री राजबीर की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं स्रो वि/जी जी एन / 26-85 / 28472 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. 1 हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज एस.सी.स्रो नं 825-26, सैक्टर 22-ए, चण्डीगढ़। 2 हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि., गुड़गांवा के श्रमिक श्री मोहन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य उसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हैतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं।

इस लिए, श्रव, श्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए ग्रिधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त ग्रिधिसूचना की धारा 7 के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रीमक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथवा संबंधित मामला है :--

क्या श्री मोहन सिंह की सेवाग्रों का समापन न्यायोजित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?